भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय परिषद बैठक
नागपुर 7–8 फरवरी, 2009
अध्यक्षीय भाषण

मित्रों पिछली बार हम लोग विगत वर्ष जनवरी 2008 में दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद में मिले थे।

मुझे याद आता है 20 जनवरी, 2006 को जब मैं दिल्ली की राष्ट्रीय परिषद में आप सबके अनुमोदन के साथ अध्यक्ष का दायित्व ग्रहण कर रहा था; तब से अब तक तीन वर्ष गुजर गये। तीन वर्ष बाद आज नागपुर में राष्ट्रीय अध्यक्षीय उद्बोधन मेरे लिए एक विशेष महत्व रखता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक बाल स्वयंसेवक के रूप में जब मैंने कभी नागपुर देखा भी नहीं था, परन्तु, नागपुर के प्रति मेरे मन में एक अनन्य अनुराग और आस्था का भाव विद्यमान था। उस मनोभाव की पृष्ठभूमि में आज नागपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी के अधिवेशन को संबोधित करते हुए मैं बहुत रोमांचित अनुभव कर रहा हूं।

ऐसा कहा जाता है कि भौगोलिक दृष्टि से नागपुर भारत के केन्द्र में स्थित है। मेरा मानना है कि नागपुर की यह धरती सिर्फ भारत के भौगोलिक ही नहीं बल्कि भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद को समर्पित अनेक आन्दोलनों का केन्द्र बिन्दु रहा है। आज से 84 वर्ष पूर्व 1925 में यहीं से राष्ट्रवाद की एक ज्योति प्रज्जवलित हुई थी जिसका प्रकाश और प्रभाव आज सारे भारत में अनुभव किया जा सकता है। यहां पूज्य डा0 हेडगेवार और पूज्य श्रीगुरूजी का पावन स्मारक आज भी प्रकाश स्तंभ के रूप में अनेकानेक राष्ट्रभक्तों का दिग्दर्शक बन कर खड़ा है। नागपुर का क्षेत्र सामाजिक समरसता के कालजयी योद्धा और संविधान निर्माता डा0 भीमराव अंबेडकर की कर्मभूमि भी रहा है। भारत के राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के इन प्रतीक पुरूषों के अभिनंदन के साथ हम इस बैठक का प्रारंभ करेंगे।

सिर्फ नागपुर या विदर्भ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की पूरी धरती शताब्दियों से भारत में राष्ट्रवाद की ध्वजावाहक रही है।

भारत के इतिहास के सर्वाधिक अंधकार के क्षणों में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा हिन्दू पदपादशाही की स्थापना करना रहा हो अथवा नाना साहब पेशवा द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करना अथवा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा पूर्ण स्वराज्य का उद्घोषण करके स्वतंत्रता आन्दोलन का श्रीगणेश करना रहा हो, अथवा स्वातंत्र्य वीर सावरकर द्वारा प्रखर राष्ट्रवाद की ज्योति जलाना हो, महाराष्ट्र की धरती ने सदैव राष्ट्रवाद के प्रकाश को प्रज्ज्वलित करने का कार्य किया।

मेरा मानना है कि महाराष्ट्र की जनता अपने गौरवशाली अतीत और भविष्य की उज्जवल संभावनाओं के अनुरूप राष्ट्रवाद के साथ भविष्य के विकास का मार्ग ही चुनेगी और इस वर्ष होने वाले लोकसभा एवं विधान सभा चुनावों में भाजपा–शिवसेना युति को पूर्ण समर्थन देगी। महाराष्ट्र तथा भारत दोनों में एक विकासोन्मुख और राष्ट्रवादी सरकार स्थापित होगी।

लोकसभा चुनाव से पहले यह अंतिम राष्ट्रीय परिषद है एवं लोकसभा चुनाव से पहले अब कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी नहीं होनी है। **हम सभी कार्यकर्ताओं का चुनाव से पूर्व यह अंतिम सामूहिक समागम है।** स्वाभाविक है कि यह आयोजन आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा नेतृत्व की एन.डी.ए. सरकार की विजय के संकल्प का प्रतीक होना चाहिए। हम सब इस अधिवेशन में इस संकल्प और विश्वास को मन में धारण करके जायेंगे कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो भाजपा नेतृत्व की एन.डी.ए. सरकार को स्थापित करके मिलेंगे।

मैं आप सभी को यह भी स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इससे पूर्व नागपुर में भाजपा की राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन 27–28 अगस्त, 2000 को हुआ था। तब हम केन्द्र की सत्ता में थे

और अगले अधिवेशन के समय हम आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में केन्द्र की सत्ता में होंगे।

विधान सभा चुनाव परिणाम

विगत नवम्बर और दिसम्बर माह में 6 राज्यों– मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, मिजोरम और जम्मू–कश्मीर के विधान सभा चुनाव संपन्न हुए। चुनावों के परिणाम हमारे लिए मिश्रित अनुभूति के रहे। जहां एक तरफ राजस्थान में अच्छी सरकार चलाकर भी हम थोड़े अंतर से कांग्रेस से पिछड़ गये वहीं दिल्ली में हमारा प्रदर्शन अप्रत्याशित रूप से प्रतिकूल रहा और कहीं न कहीं सारे देश के कार्यकर्ताओं के मानस पर इसका प्रभाव पड़ा।

जम्मू–कश्मीर में हमने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी संख्या एक से बढ़ाकर 11 की। जम्मू में भाजपा के शानदार प्रदर्शन ने अलगाववाद की मार झेल रहे इस उत्तरी राज्य में राष्ट्रवाद की पताका फहराने का कार्य किया। इस शानदार प्रदर्शन ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारे वैचारिक मुद्दों के प्रति आज भी जनता में व्यापक जनसमर्थन की संभावनाएं विद्यमान हैं। श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड, कश्मीरी हिन्दुओं के पुर्नस्थापन सहित जनहित के सभी मुद्दों पर हम जम्मू–कश्मीर की विधान सभा में सशक्त और प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।

इन चुनाव परिणामों ने भाजपा के इतिहास में कुछ शानदार अध्याय भी जोड़े। मुझे याद है कि जनवरी, 2008 में जब हम दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन में मिले थे तो गुजरात और हिमाचल की शानदार विजय के उत्साह से हम सबका मन आह्लादित था। उसी प्रकार इस राष्ट्रीय परिषद में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की विजय हम सबको एक सुखद अनुभूति दे रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की विजय ने एक मिथक को तोड़ा है कि भाजपा दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती। इससे पूर्व हम केवल गुजरात जो कि विगत 15 वर्षों से हमारा गढ़ रहा है वहीं लगातार सरकारें बनाते रहे और अपवाद स्वरूप केवल 2005 में झारखंड और 1993 में (राष्ट्रपति शासन के मध्यांतर के साथ) राजस्थान को छोड़कर हमारी किसी भी राज्य में सत्ता में वापसी नहीं हुई। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की विजय भाजपा के इतिहास में एक नये युग में प्रवेश की प्रतीक हैं। भाजपा और जनसंघ के इतिहास में पहली बार हमने एक साथ दो राज्यों में सत्ता में वापसी करने में सफलता पायी है। इस हेतु मैं इन दोनों प्रांतों की जनता, सभी भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रदेश अध्यक्षों श्री विष्णुदेव साय एवं श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, इन प्रदेशों के प्रभारी एवं चुनाव प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री रविशंकर प्रसाद, श्री अनंत कुमार, श्री वेंकैया नायडू को बधाई देता हूं। विशेष रूप से मुख्यमंत्री डा0 रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान जिनके नेतृत्व में इन प्रांतों का चुनाव लड़ा गया, उनका राष्ट्रीय परिषद की ओर से अभिनंदन करता हूं।

यदि सभी राज्यों के विधान सभा चुनाव परिणामों को हम समग्रता से देखें तो हम कांग्रेस से कहीं आगे हैं। हमारे अधिक विधायक निर्वाचित हुए हैं। परन्तु, हमें इस अनुभव से यह भी सीखना चाहिए कि हमें जनसामान्य के साथ और अधिक तारतम्य स्थापित करने की आवश्यकता है। जनता की समस्याओं के लिए और अधिक संवेदनशीलता और संघर्ष की आवश्यकता है।

आज की परिस्थितियां

मित्रों, आज केवल हम यह कहकर संतुष्ट नहीं हो सकते कि दुनिया के कुछ देश नकारात्मक विकास दर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी भी विकास दर यदि 3–4 प्रतिशत कम हो गई तो कोई चिंता की बात नहीं है। **मैं भारत सरकार के नीति–नियंताओं को यह बताना चाहूंगा कि भारत के विशाल आकार और अभी विकास की प्रारंभिक अवस्था में रहने वाली अर्थव्यवस्था के कारण यदि 1 प्रतिशत विकास दर भी कम होती है तो उसका प्रभाव लाखें लोगों की रोजी–रोटी पर पड़ता है।** एक अनुमान के मुताबिक कुछ ही समय में भारत में 1 करोड़ लोग अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे। अकेले तमिलनाडु के थिरूपुर जिले में निर्यात में कमी आने के कारण लगभग 10

लाख कारीगरों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। सूरत के हीरा उद्योग से जुड़े हुए लाखों कारीगरों के सामने भी ऐसा ही संकट दिखाई पड़ रहा है।

यदि विश्व की अर्थव्यवस्था में ऐसी समस्याएं दिख रहीं थी तो भारत सरकार ने समय रहते बचाव के कोई उपाय क्यों नहीं किए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एन डी ए सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2001–02 में भी विषम परिस्थितियां विश्व में उत्पन्न हुई थीं परन्तु हमने उसका कोई भी गुणात्मक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ने दिया था।

आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकट परिस्थितियों की दुहाई देने वाली यूपीए सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एनडीए के शासनकाल में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिति आज से अधिक विकट थी। सरकार बनने के साथ ही हम पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद आर्थिक प्रतिबंद्ध की गिरफ्त में थे और आर्थिक प्रतिबंद्ध के दौरान भी कारगिल युद्ध का सामना किया। इन सबके बावजूद हमने न विकास की दर कम पड़ने दी, न महंगाई बढ़ने दी और न बेरोजगारी बढ़ने दी। एन डी ए सरकार में आवास ऋण से लेकर कृषि ऋण तक ब्याज की दरें भी कम हुईं और शेयर मार्केट भी सुदृढ़ता के साथ निरन्तर बढ़ता रहा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज न तो देश युद्ध का सामना कर रहा और न ही प्रतिबंद्ध का। फिर भी देश आर्थिक समस्याओं से क्यों जूझ रहा है। बेरोजगारी लगातार क्यों बढ़ रही है। सिर्फ इसलिए क्योंकि इस सरकार के पास आर्थिक दूरदृष्टि का नितांत अभाव है।

इस सरकार के पास आर्थिक दूरदृष्टि ही नहीं बल्कि देश के अंदर नाक के नीचे होने वाली कारगुजारियों पर दृष्टि रखने की क्षमता भी नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व देश की प्रतिष्ठित आई.टी. कंपनी सत्यम के अंदर जिस प्रकार के आर्थिक घोटाले का पर्दाफाश हुआ, वह इस बात को प्रमाणित करता है कि तेजी से उभरती और फैलती अर्थव्यवस्था में समस्याओं को कारपोरेट जगत में नियंत्रित करने की क्षमता इस सरकार में नहीं है।

आम आदमी के साथ दावा करके केन्द्र में आयी यूपीए सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। यदि संयुक्त राष्ट्र की विकास रिपोर्ट को आधार माने तो आज भी भारत में 80 प्रतिशत लोग एक डॉलर यानी लगभग 50 रूपए से कम कमा पाते हैं। 25 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी खर्च करने की क्षमता 15 रूपए प्रतिदिन से भी कम है। लगभग 38 प्रतिशत घरों के आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं है। आधे लोग आज भी कच्चे या अनुपयुक्त घरों में रहते हैं। 43 प्रतिशत गांव आज भी स्थायी सड़क से नहीं जुड़े हैं। क्या यही आर्थिक प्रगति का वास्तविक सोपान है?

साढ़े चार साल से लगातार महंगाई के बोझ तले यूपीए सरकार के कार्यकाल में आम आदमी दबा रहा। आज सरकार कहती है कि महंगाई कम हो रही है। क्या यह सरकार के प्रयासों से कम हो रही है? यह महंगाई विश्वव्यापी मंदी के कारण कम हो रही है, यह महंगाई आम आदमी को कोई राहत नहीं दे रही है, क्योंकि इसी के साथ लगातार बेरोजगारी भी बढ़ रही है। **अमेरिका के एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक हेरीटेज फाउंडेशन और वाल स्ट्रीट जॉरनल के संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2008 में भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (इकनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स) में विश्व में 115वें नंबर पर हैं।**

इन सबके बावजूद यूपीए सरकार ने सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई लगभग सभी महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना की परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया। एनडीए सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना देश के विकास में एक मील का पत्थर बन कर आयी थी। मूल योजना के अनुसार अब तक यह परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए थी परन्तु अभी यह पूर्ण होने से बहुत दूर है। उसका कारण यह है कि **एनडीए के शासनकाल में जहां प्रतिदिन 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा था वहीं यूपीए के शासनकाल में यह प्रतिदिन 1 किलोमीटर से भी कम रहा।**

परियोजनाओं की गति ही सिर्फ धीमी नहीं हुई है बल्कि उनके वित्तीय समायोजन में भी भीषण कोताही दिखाई पड़ी है। एक अनुमान के अनुसार इस समय भारत में आधारभूत संरचना की परियोजनाओं में सैकड़ों करोड़ों रूपया केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता के मध्य फंसा हुआ है।

क्या आर्थिक मंदी के इस दौर में इतने महत्वपूर्ण इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को धीमा रखना और सैकड़ों करोड़ों रूपए लालफीताशाही में फंसा कर रखना यह देश वहन कर सकता है? देश को यह वहन करना पड़ रहा है। **यूपीए सरकार को लगता है कि ये योजनाएं एनडीए सरकार की थीं इसलिए भले ही सड़क खराब रहे या अधूरी रहे पर एनडीए सरकार को श्रेय नहीं मिलना चाहिए।** क्या यह देश के साथ छलावा नहीं है?

यह बात मैं केवल राजनीति के लिए नहीं कह रहा। बल्कि विदेशियों और चीन जैसे कम्युनिस्ट देश के आर्थिक जानकारों की भी यही राय है।

अभी कुछ दिन पूर्व चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलि ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य जो कम्युनिस्ट पार्टी की शंघाई इकाई के प्रमुख हैं, मुझ से मिलने आये थे। मैंने आर्थिक मंदी पर चर्चा करते हुए कहा कि यदि भारत बड़ी आधारभूत संरचना के प्रोजेक्ट्स को आगे रखे, जिसकी कि भारत में बहुत संभावना है, तो तमाम कंपनियां नये प्रोजेक्ट्स की तलाश में भारत आ सकती हैं। भारत को सस्ते दामों पर स्तरीय प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और इस मंदी के प्रभाव से भारत बाहर निकल सकता है। तो उन्होंने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि हम भी चीन में ऐसा ही कुछ कर रहे हैं।

परन्तु यूपीए सरकार सभी योजनाओं को केवल ठंडे बस्ते में इसलिए डाले रखना चाहती है क्योंकि उनसे एनडीए का नाम जुड़ा हुआ है।

मित्रों, अब देश की जनता विकास के साथ हो रहे इस छलावे को समझ चुकी है। अब **दोबारा एनडीए की सरकार आयेगी और इन सभी वृह्द विकास परियोजनाओं को तेजी से लागू करते हुए इस मंदी से देश को बाहर निकालेगी।**

आतंकवाद

मुझे याद आता है कि केन्द्र में यूपीए सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह जब मुंबई गये थे तो उन्होंने यह कहा था कि अपने कार्यकाल में वह मुंबई को शंघाई बना देंगे। मित्रों, गत वर्ष 26 से 29 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के दौरान रेलवे स्टेशन, अस्पताल, होटल और सड़क सब जगह जिस तरह युद्ध जैसी गोलाबारी हो रही थी उसे देख कर मुझे लगा कि क्या यही मुंबई का वह चेहरा है जिसे शंघाई बनाने की बात करने वाली यूपीए सरकार यहां तक ले आई।

अब जाकर सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून बनाने की बात मानी है। याद करिए, केन्द्र में सत्ता संभालने के तुरन्त बाद यूपीए सरकार ने जो काम सबसे पहले किए थे उनमें से एक था पोटा को समाप्त करना। अब, कार्यकाल के अंतिम चरण में उन्हें अंततः आतंकवाद विरोधी कानून पुनः लागू करना पड़ा। यह प्रमाणित करता है कि आतंकवाद के विषय पर सरकार पूरे कार्यकाल के दौरान वोट बैंक की अंधी दौड़ में भटकते हुए वापस उसी मुकाम पर आ गई है जहां के लिए हम पिछले 5 सालों से लगातार आवाज़ उठाते रहे।

पर इन साढ़े चार सालों में इसकी बहुत बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ी। विगत साढ़े चार वर्षों में यूपीए सरकार के कार्यकाल में पूरे देश में 40 से अधिक आतंकवाद की घटनायें हुईं। यानी औसतन 1.5 महीना भी बगैर किसी आतंकवादी घटना के नहीं गुजरा। इन घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गये, देश का हर कोना प्रभावित हुआ। मैं एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट ने भी वर्ष 2007 में भारत को इराक के बाद आतंकवाद से सर्वाधिक पीड़ित देश माना था। वैसे विगत 26 से 29 नवम्बर को मुंबई में हर सड़क पर जिस तरह गोलाबारी हो रही थी उसे देख कर लग रहा था मानो यह भारत का मुंबई नहीं बल्कि इराक का बगदाद शहर है।

अब जाकर सरकार नई राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात भी मान ली है। नया कानून और नई एजेंसी बनाने का विचार अब समझ में आया जब पूरा देश आतंकवाद की ज्वाला में धू–धू कर जलने लगा। आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की नीति पर मुझे संस्कृत साहित्य के महान

विद्वान भतृहरि के विख्यात नीति शतक का उद्धरण याद आता है—**"प्रोद्‌दीपते भवने, च कूप खननम्"** अर्थात ऐसे पुरूष जिनकी दूरदृष्टि ऐसी हो कि भवन में आग लगने के बाद कुंआ खोदना शुरू करें, वे समाज को विनाश की ओर ले जाते हैं। यूपीए सरकार की नीति इसी प्रकार की है।

आतंकवाद से लड़ने का संकल्प एक मुखौटा

पिछले कुछ वर्षों में देश में हर प्रमुख शहर में आतंकवादी हमला हुआ। पिछले कुछ महीनों में मुंबई के अतिरिक्त 13 सितंबर, 2008 को दिल्ली में सिल–सिलेवार बम विस्फोट हुए जिसमें 25 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। 19 सितंबर को बटाला हाउस में मुठभेड़ में जांबाज इंसपेक्टर मोहन चन्द्र शर्मा शहीद हुए, 30 अक्तूबर, 2008 को असम के चार जिलों में सिल–सिलेवार बम विस्फोट हुए जिसमें 83 लोगों की मौत हुई और 400 से अधिक लोग घायल हुए। असम में अब तक का यह सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था।

देश में यह सब कुछ हो रहा था और यूपीए सरकार के मंत्री इन्हीं दिनों क्या बयान दे रहे थे, जरा देश की जनता याद करे।

- एक केन्द्रीय मंत्री बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता देने की बात कर रहे थे।
- एक केन्द्रीय मंत्री सिमी को सांस्कृतिक संगठन बता रहे थे।
- कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के नेता आतंकवाद में निरूद्ध आरोपी के गांव तक जा कर उसके साथ हो रहे तथाकथित अन्याय की दुहाई दे रहे थे।
- सरकार के ही एक सहयोगी दल के नेता बटाला हाउस मुठभेड़ की जांच की मांग कर रहे थे, तो कांग्रेस के एक अन्य प्रमुख नेता संसद के पटल पर मुंबई के एस.टी.एफ. के अधिकारियों की शहादत पर प्रश्नचिह्न लगा रहे थे।
- कम्युनिस्ट पार्टी के एक मुख्यमंत्री मुंबई हमलों में शहीद मेजर के परिवार के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे।
- और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की नींद आस्ट्रेलिया में आतंकवाद में आरोपित एक व्यक्ति के साथ हो रही पूछताछ के कारण उड़ी हुई थी।
- प्रधानमंत्री देश के संसाधनों पर मुस्लिम समुदाय के पहले हक की वकालत कर रहे थे। हक तो गरीबों का पहला होना चाहिए वह किसी भी मजहब या जाति के हों।
- प्रधानमंत्री क्यूबा में जाकर पाकिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित देश घोषित कर रहे थे।
- और इन सारी हरकतों को यदि हम इस पृष्ठभूमि में देखें कि जो देश की संसद पर हमले में दोषी सिद्ध हो चुके आतंकवादी पर सर्वोच्च न्यायालय की सजा लागू करने में इतनी सुस्ती से चल रही थी कि तीन साल तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। वहीं, तथाकथित हिन्दू आतंकवाद का हौवा खड़ा करके राजनीति की रोटियां सेंकने के लिए इतनी तेजी से गति कर रही थी कि हर दिन जांच का एक नया चेहरा सामने आ रहा था।
- आतंकवाद के इन दो पहलुओं पर सरकार की तेजी और सुस्ती के ये दो उदाहरण अपने आप में यह साबित करने के लिए काफी हैं कि सरकार की असली फितरत क्या है।

आतंकवाद पर ऐसी नीति और नीयत रखने वाली सरकार जब आतंकवाद से निपटने की बात करती है तो यह बात सिर्फ हास्यास्पद ही नहीं बल्कि आक्रोश पैदा करने वाली लगती है।

पड़ोसी देश

भारत के पड़ोसी देशों में इस समय बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां चल रही हैं। आज हमारी आतंरिक सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ हमारी विदेश नीति एक सिक्के के दो पहलू हो गए हैं। **इसीलिए मैंने पिछली राष्ट्रीय परिषद में यह मांग की थी कि सरकार को पड़ोसी देशों के लिए एक अलग विदेश नीति बनानी चाहिए। पाकिस्तान के साथ चल रहा वर्तमान घटनाक्रम आज इस आवश्यकता को प्रमाणित कर रहा है।**

मुंबई की घटना के बाद जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान के कई संगठनों और पाकिस्तान के सरकारी तंत्र के कुछ भागों की प्रत्यक्ष सक्रियता भारत पर हो रहे आतंकवादी हमलों में दिखाई पड़ रही है। **मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह इसी पाकिस्तान को प्रधानमंत्री आतंकवाद से पीड़ित देश कह रहे थे?**

मुंबई की घटना के बाद हर दिन सरकार की तरफ से कोई न कोई बयान आता है कि मानो अब युद्ध होने ही वाला हो। फिर बयान पलटता है, फिर दो तीन दिन बाद एक और बयान आता है। यह सरकार इस तरह की बयानबाजी करके देश की जनता का ध्यान बंटा कर रखना चाहती है। हम बहुत पहले ही यह कह चुके हैं कि इन परिस्थितियों में पाकिस्तान को कोई ठोस कदम उठाना होगा और इसके लिए **भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्वास में लेकर पाकिस्तान पर पूरा कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए और यदि इसके बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलता है तो सीधी कार्यवाही का विकल्प प्रयोग करना चाहिए।**

मैं एक अन्य प्रश्न सरकार से पूछना चाहता हूं कि मुंबई पर हुए हमले के ढ़ाई महीने गुजर चुके हैं, सरकार लगातार पाकिस्तान में आतंकवादी संरचना का विषय उठा रही है परन्तु **यूपीए सरकार यह बताये कि इन ढाई महीनों में केन्द्र सरकार ने कितने आतंकवादी मॉड्यूल नष्ट किये हैं?** सरकार को देश की जनता के सामने पिछले साढ़े चार वर्षों में हुए सभी आतंकवादी हमलों में आज तक हुई जांच, अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने की स्थिति और दोषियों को सजा दिलाने में मिली सफलता की रिपोर्ट सामने रखनी चाहिए।

आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सरकार के साथ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भावी प्रधानमंत्री आदरणीय आडवाणी जी ने भी स्पष्ट रूप से इस लड़ाई में एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े रहने की बात कही थी। मैंने भी सार्वजनिक रूप से भाजपा द्वारा सरकार के सहयोग की बात कही। परन्तु केन्द्र सरकार अभी देश के बाहर तो क्या देश के अंदर भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सकी। यदि यह कहा जाय कि कि आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध में सरकार एक ढपोरशंख की तरह व्यवहार कर रही है तो अनुचित नहीं होगा।

अफगानिस्तान

अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमांत प्रांतों में हो रही गतिविधियां निश्चित रूप से चिंता का कारण है। तालिबान का प्रभाव पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और फाटा तक ही नहीं बल्कि अब पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में फैलता जा रहा है। इस प्रकार यह भारत की सीमा के नजदीक भी आ रहा है। तालिबान ने यह घोषणा की है कि युद्ध की स्थिति में वह पाकिस्तान सेना का भारत के विरूद्ध साथ देगा। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार को कोई प्रभावी कदम उठाना चाहिए।

श्रीलंका

श्रीलंका में एल.टी.टी.ई. निर्णायक पराजय के मुकाम पर है। इस बदलते परिदृश्य में श्रीलंका सरकार को पूरी संवेदनशीलता के साथ तमिलों की भावनाओं और समस्याओं को ध्यान में रख कर वार्ता के द्वारा जातीय समस्या का राजनैतिक समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। भारत सरकार को इस हेतु पूरा सहयोग देना चाहिए ताकि श्रीलंका में स्थायी शांति आ सके।

हम श्रीलंका की अंखण्डता और संप्रभुता का पूरा सम्मान करते है। परन्तु श्रीलंका में स्थाई शांति और इस समस्या का स्थाई समाधान तभी हो सकता है जब 1987 के समझौत के अनुसार श्रीलंका सरकार एक संघीय स्वरूप के अनुसार तमिल प्रान्त को शक्ति दे। **1987 के शांति समझौते में उल्लिखित श्रीलंका संविधान के तेरहवें संशोधन के अनुरूप तमिलों को शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।**

बांग्लादेश

बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। दो साल के सैनिक शासन सहित सात साल बाद हुए संसदीय चुनावों में हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की अध्यक्ष श्रीमती शेख हसीना वाजिद के नेतृत्व में आवामी लीग की नई सरकार गठित हुई है। मैं श्रीमती शेख हसीना और उनकी नई सरकार को बधाई देता हूं। हम आशा करते हैं कि नई सरकार बंगलादेश की धरती से भारत के विरूद्ध चल रहे आतंकवादी केन्द्रों को समाप्त करेगी और भारत और बांगलादेश के मध्य बेहतर संबंधों का मार्ग प्रशस्त करेगी। **शेख हसीना ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यदि बांग्लादेश इस विषय पर पूरी ईमानदारी के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करे तो हम इस क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त करा सकते हैं और शांति और समृद्धि का नया युग प्रारंभ कर सकते हैं।**

नेपाल

नेपाल में माओवादी सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सत्ता प्राप्त करने के बाद नेपाल की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर आघात करने का एक प्रयास किया है, जिसे हम सर्वथा अनुचित मानते हैं। पिछले दिनों नेपाल के विश्व प्रसिद्ध और सारे विश्व के हिन्दुओं के आस्था के एक केन्द्र भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में **जिस प्रकार न्यायालय के निर्देश के बावजूद शताब्दियों पुरानी व्यवस्था को बदलने का जबरन प्रयास किया गया उससे नेपाल की सरकार की लोकतंत्र और नेपाल की संस्कृति में आस्था संदेह के घेरे में आ जाती है।**

विषय भारतीय पुजारियों का नहीं बल्कि भारत और नेपाल के हजारों वर्ष पुराने साझा सांस्कृतिक संबंधों का भी है और ऐसे प्रयासों से इन संबंधों पर आघात पहुंचता है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए मैंने तत्काल नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' एवं नेपाल के राष्ट्रपति श्री रामबरन जी यादव से फोन पर बात की। अपनी भावनाओं से अवगत कराया और तत्काल हस्तक्षेप करके पूर्ववत् स्थिति बहाल करने का आग्रह किया।

भारत कभी भी सांस्कृतिक और धार्मिक विषयों को राजनीति से जोड़कर नहीं देखता। हमारे यहां यदि मदर टेरेसा और सिस्टर अलफोनसो को वेटिकन के द्वारा संत घोषित किया जाता है तो हम इसका विरोध नहीं करते कि यह प्रक्रिया भारतीयों द्वारा होनी चाहिए थी।

नेपाल की सरकार पशुपतिनाथ मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति के लिए एक आन्तरिक नेपाली व्यवस्था गठित करने की बात कर रही है। ताकि पुजारियों की नियुक्ति और मान्यता नेपाल की अंदर ही निर्धारित की जा सके। **मैं नेपाल की सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या वे नेपाल के आर्कबिशप या कार्डिनल की नियुक्ति भी बैटिकन द्वारा निर्धारित किये जाने का वैसा ही विरोध करके एक नेपाली व्यवस्था के तहत आर्कबिशप या कार्डिनल की नियुक्ति करने का निर्णय लेंगे जैसा प्रयास वे पशुपतिनाथ मंदिर के संदर्भ में कर रहे है**?

चीन

चीन भी लगातार अरूणाचल के सवाल को जिस प्रकार उठा रहा है वह हमारे लिए निरंतर चिंता का विषय बना हुआ है। अपने पूरे कार्यकाल में चीन के साथ बेहतर संबंधों की दुहाई देने

वाली केन्द्र सरकार एक बार भी चीन द्वारा भारत का पक्ष एकदम खारिज करने का कूटनीतिक का समुचित जबाव नहीं दे पायी।

आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने

- भारत को विश्व की महाशक्तियों की कतार में स्थापित किया था।
- सिक्किम का समाधान
- काश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग–थलग कर दिया था।
- पश्चिमी देशों में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरूद्ध होने वाले समस्त दुष्प्रचार को प्रभावहीन कर दिया था।
- कारगिल युद्ध से लेकर संसद पर आक्रमण तक के घटनाक्रम पर किसी भी दूसरे देश को प्रभावी दखलन्दाजी करने का मौका नहीं दिया था।

विदेश नीति

मित्रों, विगत कार्यसमिति से वर्तमान राष्ट्रीय अधिवेशन के बीच भारत–अमेरिकी परमाणु समझौते का अंतिम अनुमोदन हुआ। केन्द्र सरकार ने यह कहा कि भारत–अमेरिका का रणनीतिक साझीदार बन गया है। हम अमेरिका और विश्व के सभी देशों के साथ अच्छे संबंधों के पक्षधर हैं। मैंने यह मांग की थी कि यदि अमेरिका भारत का रणनीतिक साझीदार है तो अमेरिका को पाकिस्तान को दी जाने वाले आर्थिक सहायता तब तक रोक देनी चाहिए जब तक पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवादी संगठनों को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही न करे।

अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा ने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद जारी अपनी विदेश नीति के वक्तव्य में पाकिस्तान को यह निर्देश दिया है कि यदि उसने अपनी भूमि पर जारी आतंकवादी हरकतों पर रोक नहीं लगायी तो अमेरिका द्वारा उसे सहायता जारी रखना संभव नहीं होगा। परन्तु अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली असैन्य आर्थिक सहायता में बढोत्तरी की है। मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान को मिली किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी तत्वों को मजबूत कर सकती है क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान के स्टेट और नॉन स्टेट प्लेयर के बीच की रेखा बहुत अस्पष्ट होती जा रही है।

अभी अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी यह बयान दिया है कि अलकायदा का बहुत सा नेटवर्क पाकिस्तान में संभावित है और यदि ऐसे प्रमाण मिले तो अमेरिकी सेना पाकिस्तान में प्रत्यक्ष आक्रमण भी करेगी। क्या यह परिस्थिति पाकिस्तान को अतिरिक्त सहायता देने के लिए उचित है? मेरे विचार से नहीं। यद्यपि अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आथिक सहायता में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अभी पिछले सप्ताह बढ़ी हुई राशि में कुछ कटौती की है। परन्तु मेरा यह मानना है कि भारत सरकार को अमेरिका से यह आग्रह करना चाहिए कि **अमेरिका पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आर्थिक सहायता न दें।**

अमेरिका में नये राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा को अपने कार्यकाल के लिए शुभकामनायें देता हूं और आशा करता हूं कि भारत–अमेरिकी संबंध अधिक सुदृढ़ होंगे और विश्व में शांति स्थापित करने में वे और अधिक प्रभावी भूमिका निभायेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में एक और घटना हुई जिससे सभी भारतीयों को गर्व की अनुभूति हुई। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन के समय से यह परंपरा रही है कि शपथ ग्रहण करते समय राष्ट्रपति के लिए अनेक धार्मिक प्रमुख प्रार्थना करते हैं। **इस बार इस प्रार्थना में भारतीय मूल की महिला पुजारी और अमेरिका की प्रतिष्ठित डाक्टर उमा मैसूरकर भी**

अधिकृत पुजारी के रूप में शामिल हुई। यह भारतीय संस्कृति के प्रति अमेरिका और सारे विश्व में निरन्तर बढ़ते सम्मान का एक और प्रतीक है।

एनडीए के शासनकाल में वाजपेयी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जो प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाया था वह यूपीए के शासनकाल में पूरी तरह खत्म हो गया।

केन्द्रीय गृह मंत्री जिस प्रकार यह कहते हैं कि वह वाशिंगटन जाकर अमेरिका को पाकिस्तान के विरूद्ध सबूत एक बार फिर दिखायेंगे उससे लगता है कि जैसे यूपीए सरकार में भारत मानो असहाय सा हो गया है।

मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री ने यह कहा कि पाकिस्तान का सरकारी तंत्र भी मुंबई पर हुए आक्रमण में संलिप्त है। परन्तु ब्रिटेन के रक्षा मंत्री मिली बांड ने यह कह दिया कि पाकिस्तान का सरकारी तंत्र इसमें संलिप्त नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दोषियों पर कार्यवाही पाकिस्तान में होनी चाहिए जबकि भारत सरकार का आग्रह है कि कार्यवाही भारत में होनी चाहिए। इतना ही नहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया कि काश्मीर की समस्या मूल कारण है यदि इसका समाधान हो जाय तो आतंकवाद पर पूरा नियंत्रण किया जा सकता है।

यह बयान तो भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत के विरूद्ध है फिर भी भारत सरकार इस पर कोई प्रभावी विरोध दर्ज नहीं करा पाई।

झारखंड की स्थिति

मित्रों, झारखंड में वर्ष 2005 में हुए चुनावों में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आयी थी और किसी अन्य दल की सीटें हमसे आधी भी नहीं थी। हमने सरकार बनायी परन्तु फिर भी संवैधानिक सत्ता का दुरूपयोग करके केन्द्र सरकार ने जिस प्रकार वहां जनादेश का अपहरण किया और राजनैतिक उठापटक का ऐसा विद्रूप नाटक प्रारंभ किया जिसका आज तक पटाक्षेप ही नहीं हो पा रहा है। शिबू सोरेन की हार झारखंड में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की नीतियों के प्रति जनता के गुस्से का प्रमाण है। मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड के उठापटक से ऊब चुकी जनता आगामी विधान सभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनायेगी।

पूर्वोत्तर राज्य

भारत के पूर्वोत्तर राज्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अक्सर मुख्यधारा के राजनैतिक दल समुचित महत्व नहीं देते। संपूर्ण क्षेत्र में 26 लोकसभा सीटें हैं जो किसी भी मध्यम स्तर के राज्य से अधिक हैं। इस क्षेत्र की अपनी विशिष्ट परिस्थितियां हैं और उसी के अनुरूप विशिष्ट समस्याएं हैं। भाजपा पूर्वोत्तर के विकास के लिए कटिबद्ध रही है। अभी हाल ही में पूर्वोत्तर के सबसे प्रमुख राज्य असम में प्रमुख प्रतिपक्षी दल असम गण परिषद ने भाजपा के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी लोकसभा में भाजपा–अगप गठबंधन असम में शानदार सफलता प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों अरूणाचल, नगालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम और मेघालय में भी कई अन्य राजनैतिक दल हमारे साथ सहयोग करने को आगे आ सकते हैं।

पूर्वोत्तर में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण पूर्वोत्तर के अनेक जिलों का जनसंख्या स्वरूप ही बदल गया है। इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने में असम और केन्द्र की सरकारें पूरी तरह विफल रही हैं।

आज केन्द्रीय गृह मंत्री बांग्लादेशियों के वीजा की जांच और उन पर कानूनी शिंकजा कसने की बात करते हैं। पिछले पांच वर्षों से और पांच वर्ष ही नहीं बल्कि **पिछले 30 वर्षों से, जब से यह समस्या प्रारंभ हुई है कांग्रेस की प्रदेश और केन्द्र सरकारों का रवैया बांग्लादेशी घुसपैठियों के विषय पर नरम ही नहीं उल्टे घुसपैठ को बल देने वाला रहा है।**

आई.एम.डी.टी. एक्ट के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार भी लगाई। असम के राज्यपाल की रिपोर्ट में सीमापार से निर्बाध घुसपैठ का पूरा विवरण दिया गया। फिर भी सरकार ने इसे रोकने की बजाय घुसपैठियों को मदद करने के लिए फॉरेनर्स एक्ट में आई.एम.डी.टी. एक्ट के प्रावधानों को जोड़ने का प्रयास किया।

इतना ही नहीं सरकार के एक मंत्री बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थायी नागरिकता देने की बात करते हैं।

इस पूरी पृष्ठभूमि में कांग्रेस की बांग्लादेशी घुसपैठ पर सख्ती करने की बात साफ दिखाती है कि ये हाथी के दिखाने के दांत हैं, खाने के नहीं।

किसान

मित्रों, आज भारत विश्व की एक प्रमुख, बहुत बड़ी और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन गया है। फिर भी देश में 60 प्रतिशत से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए किसी न किसी रूप में कृषि पर आधारित है। इसलिए खेती और किसान का समुचित विकास हुए बगैर भारत के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना व्यर्थ है। भारत की धरती विश्व की सबसे उपजाऊ धरतियों में से एक है और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है।

ऐसे में विकास का कोई भी ऐसा मॉडल जो कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करके केवल उद्योग व सर्विस सेक्टर पर आधारित हो, भारत की वास्तविक क्षमता के साथ न्याय नहीं कर सकता। **इसीलिए मेरा यह मानना है कि किसानों के भविष्य में ही भारत का वास्तविक भविष्य निहित है।**

आज जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उच्च अधिकारियों के वेतन लाखों रूपए महीनों की तरफ पहुंच रहे हैं वहीं भारत के एक किसान का औसत मासिक खर्च के लिए आय 503 रूपए के आसपास है जो कि लगभग गरीबी रेखा के पास है। National Commission for Enterprises in the Un-organised Sector की रिपोर्ट के अनुसार देश में 83.6 करोड़ लोग 20 रूपए प्रतिदिन कमाने की क्षमता भी नहीं रखते। नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में एक औसत कृषक परिवार का कर्जा दुगुना हुआ है।

इस विदर्भ क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ने बड़े जोरशोर से प्रचार करके किसानों के लिए एक राहत पैकेज दिया था परन्तु **भारत सरकार के ही अर्थ नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी.ए.जी.) की रिपोर्ट के अनुसार उस राहत पैकेज के बाद भी विदर्भ क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या में बढोत्तरी हुई।** स्पष्ट है कि किसानों को राहत पैकेज और कर्जमाफी का कोई लाभ नहीं मिला।

यूपीए सरकार की नीतियों के चलते पिछले कुछ वर्षों में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि लगातार खेती करना महंगा होता जा रहा है। उदाहरण के लिए तेलंगाना में 5 से 7 एकड़ की खेती करने वाले किसान भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। पंजाब जैसे संपन्न प्रदेश में भी 60 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। विदर्भ क्षेत्र में 15 साल पहले जहां एक एकड़ में कपास उगाने का खर्चा लगभग 2500 रूपए था वह आज 13000 रूपए हो गया है। इसी कारण से भारी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं या बगैर किसी वैकल्पिक रोजगार के कृषि छोड़ने पर मजबूर हैं।

यूपीए सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। परन्तु मुझे इस बात का दुःख है कि आजाद भारत में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे भारत के किसानों और संपूर्ण कृषि व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए मैंने संसद का विशेष सत्र बुलाने की जो मांग की थी वह आखिरकार इस सरकार ने नहीं मानी।

कृषि के भविष्य के लिए उत्पन्न हो रही ये समस्याएं सिर्फ किसानों तक सीमित रहेंगी, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। यदि इसी प्रकार की नीतियां चलती रहीं तो आने वाले समय में हमें खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। पिछले वर्ष हमने खाद्य वस्तुओं की कमी की एक झलक देखी थी। सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीतियां हमारी खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।

युवा

मित्रों, भारत में तीन प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भाजपा। तीनों में भाजपा ही सबसे कम उम्र की पार्टी है। भाजपा की स्थापना स्वतंत्रा के बाद हुई। हमारी विचारधारा और हमारी सोच एक नये युवा भारत की सोच पर आधारित है जिसका स्वप्न स्वामी विवेकानंद और श्रीअरबिन्द जैसे युवा सन्यासियों ने देखा था और जिसके लिए भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, बाघा जतिन और वासुदेव बलवंत फड़के जैसे कितने ही युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी।

आज देश की 70 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम है। इस वर्ग को कौन संबोधित करता है, किसने युवाओं का ध्यान रखा।

एनडीए सरकार के शासनकाल में विकास के और रोजगार के जो शानदार अवसर हमने उपलब्ध कराये। एनडीए सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कई प्रतिष्ठित अंतराष्ट्रीय संस्थाओं के अनुसार वर्ष 2003–04 में भारत में सर्वाधिक रोजगार सृजित हुए। इसने युवाओं को अपनी पूरी क्षमता और प्रतिभा प्रकट करने का मौका दिया।

पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी ने जब 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विचार दिया तो यह युवा भारत के लिए लिया गया एक संकल्प था। क्योंकि आज का युवा ही 2020 और उसके बाद के भारत का नीति–नियंता होगा।

विषय सबसे पहले नई टेक्नालॉजी के प्रयोग का हो, या वेबसाइट प्रारंभ करने का हो, अथवा पूरी पार्टी को इनफारमेशन टेक्नालॉजी से जोड़ने का हो, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर रहे युवाओं के साथ तारतम्य बैठाने में भाजपा सदैव शेष दलों से आगे रही।

परन्तु देश के युवाओं का तीन–चौथाई हिस्सा आज भी या तो ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में झुग्गी–झोपड़ी में रहते हुए छोटे–मोटे रोजगार से गुजारा कर रहा है। युवा वर्ग का वर्णन करते समय हम अक्सर युवाओं के इतने बड़े भाग को भूल जाते हैं। हमें युवाओं के इस वर्ग पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

आज देश में युवा शक्ति की अभिव्यक्ति के दो विपरीत स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। एक बंगलौर, चेन्नई और हैदराबाद में युवा साफ्टवेयर इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के रूप में भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर प्रतिष्ठा दिला रहा है तो दूसरा कश्मीर और देश के अनेक भागों में आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होकर देश के लिए नई समस्याएं पैदा कर रहा है।

देश की युवा शक्ति का सृजनात्मक स्वरूप आई.टी. सुपर पावर के रूप में भारत को विश्व स्तर पर स्थापित करके 1990 के दशक के अंतिम वर्षों और 2000 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में उभर कर आया। यह मार्ग एनडीए सरकार के दौरान प्रशस्त हुआ।

दूसरी तरफ पूरे देश में आतंकवाद की शुरूआत 1980 के दशक में कांग्रेस के शासनकाल में हुई जब कांग्रेस श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में दो तिहाई और तीन चौथाई बहुमत की सरकार लेकर शासन कर रहे थे।

इससे यह स्पष्ट है कि युवा शक्ति को जागृत करके सही दिशा देने की क्षमता सिर्फ भाजपा में ही है।

गांधी और आज की कांग्रेस

भविष्य के महान् भारत के विकास का मॉडल युवाओं की जिस शक्ति पर आधारित होना चाहिए उसका उल्लेख मैने कल कार्यसमिति में किया था। भारत के युवाओं के लिए आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास का एक मॉडल महात्मा गांधी और पं0 दीनदयाल जैसे विचारकों ने दिया था।

मैंने कल यह भी कहा था कि सौ वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिन्द स्वराज्य में किस प्रकार का विकास का मॉडल भारत के भविष्य के लिए वर्णित किया है।

गांधी ने अपने दर्शन में यह स्पष्ट कहा है कि भारत के भविष्य के लिए कर्मवाद का सिद्धांत परम आवश्यक है। यहीं भारत के युवाओं को सही दिशा में ले जा सकता है। गांधी का कर्मवाद पूर्णरूप से गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण स्वराज्य के उद्घोषक और वास्तविक अर्थो में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की राजनैतिक यात्रा के जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी पुस्तक ''गीता रहस्य'' ने गीता के सिद्धांतों को ''कर्मयोग शास्त्र'' की संज्ञा दी है। महात्मा गांधी राजनीति में भी तिलक की विरासत को लेकर आगे बढ़े थे। शायद आज की कांग्रेस अपने आचरण में गीता पर आधारित तिलक के कर्मयोग शास्त्र और गांधी के कर्मवाद को लागू करना तो दूर शायद आज गीता का नाम लेने में भी घबरा जाये। कि कहीं कोई उन्हें साम्प्रदायिक न कह दें।

गांधी के उन मूल्यों और विचारों का कोई भी लक्षण आज की कांग्रेस में नजर नहीं आता है। **मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 50 वर्षो तक देश को जिन नीतियों पर चलाया उसमें गांधीवाद कितना था। कांग्रेस की नीतियों में ब्रिटिश राज का तत्व अधिक था गांधी के हिन्द स्वराज्य का तत्व गायब था।** आज कांग्रेस के आचरण में गांधी के चिंतन का क्या है? आज की कांग्रेस के चिन्तन में न हिन्द स्वराज्य है, न ग्राम स्वराज्य है, न गांव का स्थान है, न किसान का सम्मान है, न स्वदेशी कुटीर उद्योग है, न त्याग और वैराग्य का जीवन जीने वाला उनसे जुड़ा कोई वर्ग है। न स्वदेशी शैली है, न स्वदेशी भाषा है। और इतना ही नहीं गांधी के कर्मवाद की प्रतीक गीता साम्प्रदायिक है, गांधी के राम राज्य में राम भी साम्प्रदायिक है। गांधी का भजन चाहे ''रघुपति राघव राजा राम'' हो अथवा ''वैष्णव जन ते तेने कहिए'' हो यह सब तो घोर साम्प्रदायिक है। गांधी के विचारों पर आधारित यह सब यदि आपको आज भी कहीं देखने को मिलेगा तो भाजपा की सोच और हमारे परिवार के कई संगठनों की सादगीपूर्ण जीवनशैली में।

मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास गांधी का क्या है आज तो गांधी की खादी भी शायद ही कोई बड़ा नेता पहनता हो। आज कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार से जुड़ा गांधी का नाम है और गांधी से जुड़ा कुछ भी नहीं बचा है। **गांधी से जुड़े सारे काम आज भी यदि कहीं दिखेंगे तो कांग्रेस के उस परिवार में नहीं बल्कि हमारे परिवार में। वहां सिर्फ नाम है यहां वास्तविक काम है।**

महिला

भाजपा आधी आबादी की समुचित भागीदारी को लेकर गंभीर है। पार्टी नारी मुक्ति नहीं, नारी शक्ति में विश्वास करती है। आज भी महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गत छह दशकों में महिला साक्षरता बढ़ी है लेकिन इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी आज भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। विधायिका में 33 फीसद महिला आरक्षण हमारी निष्ठा का प्रश्न है। एनडीए सरकार के समय हमने इस विधेयक को दो–दो बार प्रस्तुत किया, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के विरोध के कारण यह अमल में नहीं आ पाया। राजनीति में महिला भागीदारी यह केवल बौद्धिक प्रपंचों का हिस्सा नहीं है। हमने अपने संगठन में 33 प्रतिशत महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित कर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। भाजपा ने अपनी कथनी और करनी की प्रामाणिकता सिद्ध की है। हमने भाजपा शासित प्रदेशों में भी पंचायत और नगर निकाय स्तर पर 50 फीसदी महिला आरक्षण को अमलीजामा पहनाया है।

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी और भाजपा का अनुसूचित जाति मोर्चा सदैव से ही प्रत्यशील रहा है। हमारी सरकारों ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया था।

अनुसूचित वर्ग के मन में विकास के अतिरिक्त एक अन्य भावना भी रहती है और वह है अपने प्रति मान–सम्मान की भावना। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव अनुसूचित जाति वर्ग के मान–सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अनेक महत्वपूर्ण पदों पर चाहे वह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो अथवा केन्द्रीय मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, हमने हर स्थान पर अनुसूचित जाति वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व दिया है।

श्रीराम जन्मभूमि और रामसेतु

यूपीए सरकार के कार्यकाल के पांच वर्ष गुजर गये परन्तु **मुझे यह कहते हुए बहुत दुख और कष्ट का अनुभव होता है कि पांच साल में श्रीराम जन्मभूमि समस्या के समाधान के लिए 5 मिनट की वार्ता का समय भी इस सरकार ने नहीं निकाला।** किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किया गया। उल्टे श्रीराम सेतु के संदर्भ में दायर हलफनामे में सरकार ने मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम के अस्तित्व को ही नकार कर ऐसा कारनामा किया जो इस देश में विदेशी शासकों ने भी करने की हिम्मत नहीं दिखाई।

हमारे सांस्कृतिक मान बिन्दुओं का जैसा अपमान इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है वैसा संभवतः भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ।

आप याद करें कि अध्यक्ष के रूप में 20 जनवरी, 2006 को दिल्ली में अपनी पहली राष्ट्रीय परिषद में मैंने इजरायल की वीलिंगवाल का उदाहरण दिया था। आज मैं एक अन्य उदाहरण देता हूं। **यदि आप बैंकाक जायें तो वहां के नये एयरपोर्ट का नाम स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट में प्रवेश करते ही आपको अपने सामने बेहद सुन्दर मूर्तियों से बना हुआ विष्णु पुराण और देवी भागवत में उल्लिखित सागर मंथन का दृश्य बना हुआ दिखेगा। आप कल्पना करें कि यदि ऐसा प्रस्ताव भारत के किसी एयरपोर्ट के लिए आये तो तमाम तथाकथित सेक्युलरवादियों को उसमें साम्प्रदायिकता नजर आने लगेगी।** इससे पूर्व श्रीलंका की सरकार राम और रामायण से जुड़े सभी स्थलों को प्रामाणिक मान चुकी है।

दुःख का विषय है कि हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का सम्मान देश के बाहर है परन्तु देश में उसी सम्मान की स्थापना के प्रयास को साम्प्रदायिक माना जाता है। **आजादी के 60 साल बाद, अब तो कम से कम भारतीयों को आत्मग्लानि उत्पन्न करने के लिए लायी गई इस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आना चाहिए।**

चन्द्रयान की सफलता

मित्रों, विगत दिनों भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अपने कौशल और तपस्या से एक नया इतिहास रचा। जब भारत ने अपना प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चांद पर भेजा। इसके साथ ही भारत चन्द्रमा तक अभियान करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया। इस ऐतिहासिक सफलता के लिए मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष जी. माधवन नायर और उनके सभी साथी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अभिनन्दन करता हूं और बधाई देता हूं। भाजपा के लिए यह और अधिक गर्व का विषय इसलिए भी है कि क्योंकि इस परियोजना का प्रारंभ अटल जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार द्वारा किया गया है।

एनडीए बनाम यूपीए

मित्रों, आज देश में दो प्रकार के गठबंधनों के मध्य राजनैतिक ध्रुवीकरण दिखाई पड़ रहा है। एक, कांग्रेस नेतृत्व का यूपीए गठबंधन और दूसरा भाजपा के नेतृत्व का एनडीए गठबंधन।

जहां यूपीए गठबंधन अवसरवादिता, स्वार्थपरता और अंतर्विरोध से भरा हुआ एक गठबंधन है जिसने अपने कार्यकाल में देश को व्यापक क्षति पहुंचाई है।

वहीं एनडीए गठबंधन एक सकारात्मक एवं स्थायी गठबंधन के रूप में पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा है। हमारे गठबंधन सहयोगियों का भाजपा के साथ सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन 20 वर्ष से अधिक पुराना है। जनता दल–यू से हमारा गठबंधन चौदह वर्ष पुराना है। शिरोमणि अकाली दल से हमारा गठबंधन बारह वर्ष पुराना है और बीजू जनता के साथ गठबंधन का भी एक दशक पूर्ण हो गया है। क्या कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगियों को इतने लंबे समय तक साथ रख पायी है?

हाल ही में भाजपा के साथ कुछ नये सहयोगी भी जुड़े हैं। हरियाणा में श्री ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाला इंडियन नेशनल लोकदल ने भाजपा के साथ गठबंधन और एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया है। असम में असम गण परिषद ने भाजपा के साथ आगामी लोकसभा और विधान सभा चुनावों में गठबंधन का ऐलान किया है। एनडीए का और अधिक विस्तार आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा।

एनडीए के शासनकाल में देश की बेहतर स्थिति और यूपीए के शासनकाल में बदत्तर स्थिति के उदाहरण आपके सामने हैं।

आर्थिक

- एनडीए ने 6 वर्ष तक लगातार **महंगाई** रोकी। यूपीए ने साढ़े चार वर्ष तक लगातार महंगाई बढ़ाई।
- एनडीए ने **कृषि और आवास ऋण पर ब्याज दरें** घटाई। यूपीए ने बढ़ाई।
- एनडीए के समय देश के **खाद्यान्न भंडार** भरे थे। यूपीए के समय खाद्यान्नों का संकट था।
- एनडीए के समय **रोजगार** बढ़े। यूपीए के समय बेरोजगारी बढ़ी।
- एनडीए के समय कोई **आर्थिक घोटाला** नहीं हुआ। यूपीए के समय खाद्यान्न घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, सत्यम् घोटाला जैसे अनेक घोटाले हुए।
- हमने विकासोन्मुख **प्रचुरता की अर्थव्यवस्था** दी। यूपीए ने मंदी और घाटे की अर्थव्यवस्था दी।

सुरक्षा संबंधी

- एनडीए ने आने के साथ ही **आतंकवाद विरोधी कानून** पोटा लगाया। यूपीए ने हटाया।
- एनडीए ने पोकरण विस्फोट के द्वारा **भारत की सामरिक शक्ति** को स्थापित किया। यूपीए ने न्यूक्लियर डील के द्वारा उसका समर्पण किया।

राजनैतिक

- एनडीए ने **सबको न्याय** दिया। यूपीए ने अंधे **तुष्टीकरण की पराकाष्ठा** दिखाई।
- एनडीए ने **संवैधानिक मूल्यों की गरिमा** को संरक्षित किया। यूपीए ने उसे ध्वस्त किया (जैसे बिहार, झारखंड, गोवा आदि के विषय में)।
- यूपीए सरकार के पूरे कार्यकाल में केवल 322 दिन संसद चली। **एक पूरे कार्यकाल में यह भारत के संसदीय इतिहास में सबसे कम दिन संसद का सामना करने वाली सरकार है।**
- एनडीए ने भारत की **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा** बढ़ाई। यूपीए ने घटाई।

- एनडीए ने कभी **भ्रष्टाचारियों की राजनैतिक मदद** नहीं की। यूपीए के समय क्वात्रोची तक को पैसा लेकर भागने का मौका दिया गया।
- एनडीए ने **1 वोट से अपनी सरकार जाने दी** थी। यूपीए ने संसद में **नोटो से वोट खरीदने** का का कार्य किया।

विकास संबंधी

- एनडीए ने **आधारभूत संरचना की बड़ी परियोजनाएं** प्रारंभ की। यूपीए ने उन्हें धीमा किया या ठंडे बस्ते में डाला।
- एनडीए ने भारत को आणविक शक्ति, अंतरिक्ष विज्ञान, संचार माध्यम और **सूचना प्रौद्योगिकी में एक महाशक्ति** के रूप में स्थापित किया। यूपीए ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया।

सांस्कृतिक

- एनडीए ने पाठ्यपुस्तकों में **धार्मिक महापुरूषों के विरूद्ध आपत्तिजनक अंश** हटाये। यूपीए ने ऐसे संदर्भ जोड़े।
- एनडीए ने **सांस्कृतिक मूल्यों** का सम्मान किया। यूपीए ने सांस्कृतिक मान बिन्दुओं का अपमान किया (जैसे वन्देमातरम् पर रोक, रामसेतु और श्री अमरनाथ भूमि विवाद)।

यूपीए सरकार के पूरे कार्यकाल को देखें तो विकास गया, रोजगार गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा गई, सुरक्षा गई, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और इन सबके साथ राम को भी यह सरकार नकार गई। यदि एक वाक्य में कहा जाय।

''यूपीए सरकार ने किया काम तमाम।

आम आदमी को न माया (अर्थव्यवस्था) मिली न राम''।

इस तुलना के बाद देश की जनता स्वयं निर्णय ले सकती है कि देश का भविष्य किस गठबंधन के हाथ में सुरक्षित है। **मैं यूपीए गठबंधन की सरकार को चुनौती देता हूं कि वह कोई एक कार्य भी ऐसा बतायें जिससे उनके कार्यकाल में भारत के भविष्य के लिए कोई शानदार ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है।**

यूपीए के प्रति जनता का यह आक्रोश पिछले वर्षो के दौरान दिखाई पड़ा। **विगत दो वर्षो में 17 राज्य विधान सभा के चुनाव हुए। जिनमें से 11 राज्यों में यूपीए हारा और कांग्रेस को अपने बल पर केवल चार राज्यों में विजय हासिल हुई।**

एनडीए ने सर्वसम्मति से भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। आदरणीय आडवाणी जी आज देश के वरिष्ठतम एवं सर्वाधिक अनुभवी नेताओं में ही नहीं है बल्कि उन्होंने अपने 50 वर्षों से अधिक के राजनैतिक जीवन में निष्कलंक रहते हुए जिस प्रतिबद्धता और निष्ठा का परिचय दिया है वह हम सब के लिए अनुकरणीय है और पथ–प्रदर्शक है। **निश्चित रूप से किसी भी अन्य गठबंधन व दल के पास इस तरह का दूरदर्शी और परिपक्व नेतृत्व नहीं है जैसा कि आदरणीय आडवाणी जी के रूप में एनडीए के पास है।**

कार्यकर्ता

विगत तीन वर्षों में हम सबने मिलकर भाजपा को अनेक परिस्थितियों में से आगे बढ़ते हुए आज अपनी स्थिति पूरे देश में बहुत व्यापक और प्रभावी बना ली है।

हमने भौगोलिक व राजनैतिक विस्तार ही नहीं किया बल्कि संगठनात्मक विस्तार में भी एक नया अध्याय जोड़ा है। इतिहास में पहली बार बूथ स्तर की कमेटियों का गठन हुआ है। आज पूरे

देश में 65 प्रतिशत से अधिक बूथों पर भाजपा की इकाईयां गठित हो चुकी हैं। अनेक राज्यों में 90–95 प्रतिशत से अधिक बूथ कमेटियां गठित हो चुकी हैं, जैसे, गुजरात, हिमाचल आदि।

आज हम लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुके हैं। आगामी लोकसभा भाजपा के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट चुनाव होगा। अपनी स्थापना के बाद 1980 के दशक में हमने जो चुनाव लड़े उस समय हमारी राष्ट्रीय राजनीति में कोई विशेष भूमिका नहीं थी। 1989 से 1999 तक के चुनाव हमने या तो विचारधारा पर लड़े या अटल जी को मौका दिये जाने के विषय पर लड़े। 2004 का चुनाव हमने विकास को मुद्‌दा बनाकर लड़ा। 2009 का चुनाव हमारे लिए तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। **यानी आगामी चुनाव में हमें एक समेकित (इंटीग्रेटिड) रणनीति बनानी होगी। अपने वैचारिक धरातल, सुशासन की क्षमता और गठबंधन और संगठन की शक्ति को सम्मिलित करके हम निश्चित रूप से चुनाव में जनसमर्थन प्राप्त करेंगे।**

आज भारत पर देश के अंदर से संकट है, सीमापार से संकट है, अर्थव्यवस्था पर संकट है, पूंजी का संकट है, और इन सबके साथ–साथ राजनैतिक दलों में विश्वसनीयता का संकट है। भारत में सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के ऊपर भी भूमंडलीकरण के कारण एक प्रकार का सांस्कृतिक संकट है।

और अब यह सांस्कृतिक संकट इतना व्यापक रूप लेता जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियों में देश के पूर्वजों के प्रति असम्मान और उपेक्षा का भाव उत्पन्न होने का संकट भी दिखने लगा है। अभी नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर विगत 23 जनवरी को मैं एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि आज के बच्चों में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो जानता ही नहीं कि नेता जी कौन हैं। किसी बालक ने उत्तर दिया कि वह कैबिनेट मंत्री थे तो किसी ने कहा कि पुलिस अधिकारी। कहने का भाव यह है कि हम आजादी के बाद के सबसे बड़े संक्रमणकाल से गुजर रहे हैं। चुनाव के समय ये परिस्थितियां हमारे लिए एक चुनौती भी है और अवसर भी है। सारे देश की निगाह इन चुनौतियों का उत्तर देने के लिए हमारे ऊपर टिकी हुई है। यदि भाजपा इसका उत्तर नहीं दे पायी तो तय मानिए किसी अन्य दल के पास इसका कोई समाधान नहीं है।

यदि हम संगठन के पूरी शक्ति को एकजुट करके इस चुनाव में सफलता प्राप्त कर सके और इन चुनौतियों का उत्तर देश को दे सके, **इन तमाम संकटों से देश को निकाल सकें तो हम भावी इतिहास के एक शिल्पकार के रूप में जाने जायेंगे।**

मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब भाजपा के कार्यकर्ता अंततः इसमें सफल होंगे और इन चुनावों में सफलता प्राप्त करेंगे और आगामी 15 अगस्त को आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

"सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है।

सब नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है।"